

राजस्थान में बसपा का विस्तार और प्रभाव

डॉ. पूरण चन्द जाट
सह आचार्य, राजनीति विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली

राजस्थान की दलीय व्यवस्था में कांग्रेस और भाजपा दो महत्वपूर्ण ध्रुव ह। भारत के अधिकांश राज्यों से भिन्न यहां पर पिछले दो दशकों में तीसरी ताकत नहीं उभरी लेकिन दलित पार्टी के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बना चुकी बहुजन समाज पार्टी की संभावना यहां तीसरी ताकत के रूप में दिखाई देती है क्योंकि भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों के समर्थन का आधार विचारधारा गत कम और जाति आधारित अधिक है। भारतीय समाज में अनुसूचित जाति सभी जगह पाई जाती हैं। बसपा अपनी इसी दलित पहचान के आधार पर राजस्थान में अपने प्रभाव विस्तार में निरंतर प्रयत्नशील है। बसपा ने अपने गठन के 5 वर्ष बाद 1989 में राजस्थान में राज्य इकाई का गठन किया। गठन के लगभग एक दशक तक बसपा का प्रादेशिक संगठनात्मक ढांचा ढीला ढाला सीमित व कमजोर ही रहा किंतु उत्तर प्रदेश को प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर बसपा ने राजस्थान में संगठनात्मक निवेश को बढ़ाया।

कांग्रेस बसपा के विस्तार से अधिक सजग दिखाई देती है क्योंकि राजस्थान में अनुसूचित जाति को कांग्रेस के समर्थन का परंपरागत आधार माना जा रहा है। यद्यपि आरंभ में बसपा नेतृत्व का ध्यान राजस्थान की ओर अपेक्षाकृत कम ही रहा किंतु पिछले एक दशक से बसपा ने राजस्थान में अपने प्रभाव के विस्तार हेतु अधिक ध्यान दिया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र स्तर तक अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया है। भारतीय समाज में बसपा ने प्रारंभ में बहीवे"गी दश की राजनीति कर दलितों को ध्रुवीकृत करने की राजनीति के चलते प्रारंभ में बसपा राजस्थान में अपना विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाई किंतु 2002 के बाद बसपा ने बहीवे"गी राजनीति को त्यागकर अन्य जातियों को अपन साथ जोड़ने के लिए समावेशी राजनीति का उत्तर प्रदेश में विशेष प्रयोग किया। बसपा की इस नीति के कारण उसकी दलित कट्टरपंथी पार्टी की पहचान की धार अपेक्षाकृत कमजोर हुई। बसपा ने अपनी

इस समावेशी राजनीति का प्रयोग राजस्थान में भी किया जिससे उसको लाभ मिला और अपने प्रभाव में अपेक्षाकृत सकारात्मक वृद्धि की हैं।

राजस्थान में बसपा के निरंतर बढ़ते प्रभाव से तोन महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होते हैं। प्रथम— राजस्थान में तीसरी ताकत के रूप में बसपा की क्या संभावनाएं ह ? द्वितीय— बसपा के बढ़ते प्रभाव में राजस्थान की दलीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? तीसरा— राजस्थान की दलीय व्यवस्था के दो ध्रुव कांग्रेस व भाजपा में से बसपा का विस्तार किस दल के लिए घातक होगा ?

राजस्थान में बसपा की संभावनाओं के आकलन के लिए पिछले निर्वाचकीय परिणामो पर दृष्टिपात करने पर बेहद रोचक तथ्य सामने आते हैं। विधानसभा निर्वाचन में बसपा की बढ़ती प्रभावशीलता को सारणी 1 में दर्शाया गया है

सारणी 1 :- विधानसभा निर्वाचन में बसपा की प्रभावशीलता

वर्ष	प्रत्यार्थियों की सं.	विजयी सीट	मत प्रतिशत	निर्वाचन वाली सीटों से प्राप्त मत
1990	57	0	0.79	2.54
1993	50	0	0.56	2.01
1998	108	2	2.17	3.81
2003	124	2	3.97	6.40
2008	199	6	7.60	7.66
2013	199	3	3.37	6.70

स्रोत – राज्य निर्वाचन विभाग

राजस्थान में बसपा की संभावनाओं को निर्वाचन में उसकी प्रभावशीलता के द्वारा आकलन करने का प्रयास किया है। निर्वाचन में बसपा की प्रभावशीलता के विश्लेषण के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रथम— बसपा ने कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। द्वितीय— कितनी सीटों पर विजय रही। तृतीय— कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया। चतुर्थ — चुनाव लड़ी गई सीटों पर कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया।

अपने गठन के बाद बसपा ने सर्वप्रथम 1990 के विधानसभा निर्वाचन में भागीदारी की और 57 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारे। 1993 के विधानसभा निर्वाचन में 50, 1998 के निर्वाचन में 108, 2003 के निर्वाचन में 124 और 2008 के निर्वाचन में 199 और 2013 के निर्वाचन में 199 सीटों पर चुनाव लड़ा। आरंभ में सभी सीटों पर निर्वाचन में प्रत्याशी न उतारना यह दर्शाता है कि 1990 के दशक में राजस्थान में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा व्यापक नहीं था और केवल सीमित स्थानों पर ही पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे।

राजस्थान विधानसभा निर्वाचन में बसपा के प्रत्याशियों की संख्या क्रमिक चुनाव में बढ़ती गई और 2008 के निर्वाचन में यह संख्या 200 हो गई हालांकि 1 सीट पर प्रत्याशी की निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने पर पार्टी ने 199 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2013 के निर्वाचन में भी 199 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारे। राजस्थान में कांग्रेस व भाजपा के अलावा बसपा तीसरी ताकत थी जिसने लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार। इससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि पार्टी का पूरा प्रदेश में एक संगठनात्मक ढांचा तैयार हो गया है जो पूरे प्रदेश में उसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। जहां तक विजयी सीटों का सवाल है तो 1990 व 1993 के प्रथम दो निर्वाचन में बसपा को कोई सीट नहीं मिली किंतु 1998 के निर्वाचन में बसपा ने सर्वप्रथम 2 सीटें जीती और राजस्थान विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2003 में संपन्न 12वीं विधानसभा में बसपा ने अपनी पूर्व की स्थिति को कायम रखा। 2008 में तेरहवीं विधानसभा निर्वाचन में बसपा ने विधानसभा में अपनी संख्या में 3 गुना

वृद्धि दर्ज की। बसपा के 6 प्रत्याशी निर्वाचित हुए और 10 प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रह। 2013 के विधानसभा निर्वाचन में बसपा के 3 प्रत्याशियों को सफलता मिली।

लेकिन किसी दल की प्रारंभिक अवस्था में उसकी प्रभावशीलता व संभावनाओं के आंकलन के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसने निर्वाचन में कितनी सीटें जीती है बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि उसने कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया है और जिन सीटों पर चुनाव लड़ा है उन पर कितने प्रतिशत मत मिले ह। बसपा ने राजस्थान में अपन शुरुआती दौर में सीमित प्रत्याशी मैदान में उतारे और कुल मतों का 1 प्रतिशत से कम तथा मुकाबले वाली सीटों पर 2 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त किए। 1998 में बसपा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कुल मतों का 2 प्रतिशत से अधिक तथा मुकाबले वाली सीटों पर लगभग 4 प्रतिशत समर्थन प्राप्त किया। 12वीं व 13वीं विधानसभा निर्वाचन में यह समर्थन बढ़ा और तेरहवीं विधानसभा में पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़कर कुल मतों का 7.6 प्रतिशत समर्थन प्राप्त किया और पार्टी ने तीसरी व निर्णायक शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइ। प्रदेश में बसपा के संगठनात्मक आधार व समर्थन का न्यूनतम स्तर जो उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, के आधार पर यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं होगा कि बसपा राजस्थान में निर्णायक ताकत के रूप में उभर रही है और उसकी महत्वपूर्ण संभावनाएं ह।

जहां तक राजस्थान की दलीय व्यवस्था पर प्रभाव का प्रश्न है तो यह बसपा के समर्थन में उत्तरोत्तर वृद्धि से स्पष्ट है कि बसपा एक महत्वपूर्ण तीसरी ताकत के रूप में उभर रही है। 1990 के बाद राजस्थान की दलीय व्यवस्था प्रतिस्पर्धी द्विदलीय व्यवस्था के रूप में उभरी है। इन दोनों प्रतिस्पर्धी दला म दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। भारत में जहां गुजरात मध्यप्रदेश और राजस्थान को छोड़कर शेष भारत में क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों के साथ प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल है, वहीं राजस्थान में कोई क्षेत्रीय दल नहीं पनप सका। बसपा का बढ़ता जनसमर्थन निश्चय ही यहां की दलीय स्थिति को निर्णायक रूप से प्रभावित करेगा। राजस्थान की प्रतिस्पर्धी दलीय व्यवस्था में यह एक निर्णायक सीमा चिन्ह होगा। बसपा की बढ़ती संभावना राजस्थान को संक्रमणकालीन स्थिति की ओर ले जाने की ओर संकेत करती हैं, जहां

गठबंधन की राजनीति और राजनीतिक अस्थिरता की संभावनाएं पैदा होगी। यदि बसपा आने वाले निर्वाचनों में 10 प्रतिशत या उससे अधिक जनसमर्थन प्राप्त कर लेती है तो ऐसी परिस्थितियों बनने की अधिक संभावनाएं बनती हैं। बहुजन समाज पार्टी का भी यही लक्ष्य है कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आए और सत्ता में भागीदारी मिल।

यह प्रश्न बेहद कठिन है कि बसपा के जन समर्थन में विस्तार से भाजपा व कांग्रेस में से किस दल के समर्थन में गिरावट आएगी और किस सीमा तक आ सकती है, यद्यपि प्रथम दृष्टा यह आकलन किया जा सकता है कि बसपा की पहचान एक दलित पार्टी के रूप में है और उसके विश्वसनीय समर्थन का मुख्य आधार अनुसूचित जातियां हैं। राजस्थान में राजनीतिक दलों के सामाजिक समर्थन में दलितों का झुकाव कांग्रेस की तरफ माना जाता है अतः बेहद सरल व स्वाभाविक निष्कर्ष यही निकलेगा कि यदि बसपा के समर्थन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है तो कांग्रेस का जनसमर्थन घटेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कमजोर होने के पीछे दलित समर्थन का घटना एक मुख्य कारण रहा है किंतु यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान में दलितों का उस सीमा तक धुवीकरण नहीं हुआ जितना कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभ में देखा गया है। सारणी 2 में बसपा द्वारा आरक्षित व सामान्य सीटों पर पिछले तीन निर्वाचनों में प्राप्त जनसमर्थन को दर्शाया गया है। इस आधार पर हम बसपा के समर्थन के सामाजिक आधार का विश्लेषण करने का प्रयास कर सकते हैं। 2003 के निर्वाचन में बसपा ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 34 विधानसभाओं में से 19 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे और 2.7 मत प्राप्त किए। 2008 के निर्वाचन में बसपा ने दलितों के लिए आरक्षित सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए और 6.1 प्रतिशत मत प्राप्त किए यद्यपि बसपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में से एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई किंतु अपने समर्थन में दुगने से अधिक वृद्धि की। यहां यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि बसपा ने दलितों के लिए आरक्षित एक भी सीट पर सफलता प्राप्त क्यों नहीं की जबकि उसने 2003 व 2008 के निर्वाचन में जनजाति व सामान्य वर्ग की सीटों पर सफलता प्राप्त की थी। इस प्रश्न को हम सामाजिक अभियांत्रिकी के द्वारा समझ सकते हैं क्योंकि राजस्थान में बसपा अपनी शैशव अवस्था में है और उसके सामाजिक समर्थन की प्रारंभिक स्थिति समांगी प्रकृति

की है जिसके कारण वह दलितों के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में अन्य जातियों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने में असफल रही है, साथ ही यह तथ्य यह भी दर्शाता है कि दलितों के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में बसपा के इस जन समर्थक का अधिकांश भाग दलितों में आता है क्योंकि बसपा की पहचान प्राथमिक रूप से दलित समर्थक पार्टी के रूप में है। पिछले दो विधानसभा निर्वाचनों में बसपा के समर्थन में सर्वाधिक बढ़ोतरी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर देखने को मिली है जो दलितों में बसपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता की ओर संकेत करती है।

सारणी –2 :- विधानसभा निर्वाचन में बसपा की वर्गानुसार सीटों पर प्रदर्शन

वर्ग	2003				2008			2013		
	कुल सीट	प्रत्याशी	मत	विजय	प्रत्याशी	मत	विजय	प्रत्याशी	मत	विजय
एस.सी	34	19	2.7	0	34	6.1	0	34	5.70	0
एस.टी.	25	12	2.9	0	25	4.7	1	25	4.1	0
सामान्य	141	93	4.4	2	140	8.4	5	140	6.9	3

स्रोत – राज्य निर्वाचन विभाग

जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर 2003 के निर्वाचन में 12 प्रत्याशी खड़े किए और 2.9 प्रतिशत मत प्राप्त किए। 2008 के निर्वाचन में सभी 25 जनजाति सीटों पर बसपा ने प्रत्याशी खड़े किए और 4.7 प्रतिशत मत प्राप्त किए। 2008 के निर्वाचन में बसपा ने एक सीट पर जीत हासिल की यद्यपि बसपा ने जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर अन्य वर्ग की सीटों की अपेक्षा कम समर्थन प्राप्त किया इससे यह स्वभाविक निष्कर्ष निकलता है कि जनजातियों में बसपा की स्वीकारोक्ति अन्य वर्गों की अपेक्षा सर्वाधिक कम है। जबकि 2008 के निर्वाचन में जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर स्वतंत्र प्रत्याशियों ने लगभग 20 प्रतिशत मत प्राप्त कर 4 सीटों पर विजय हासिल की।

बसपा को सर्वाधिक सफलता सामान्य वर्ग की सीटों पर मिली है। 2003 के विधानसभा निर्वाचन में बसपा ने 93 प्रत्याशी खड़े किए और 4.4 प्रतिशत जनसमर्थन प्राप्त किया। 2003 के निर्वाचन में बसपा ने सामान्य वर्ग की 2 सीटों पर राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2008 के निर्वाचन में बसपा ने सामान्य वर्ग की 140 सीटों पर चुनाव लड़ा और आरक्षित वर्ग की सीटों की अपेक्षा सर्वाधिक 8.4 प्रतिशत मत प्राप्त किए। सामान्य वर्ग की सीटों पर बसपा के समर्थन में लगभग दुगनी वृद्धि दर्ज की गई और 5 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी निर्वाचित हुए। सामान्य वर्ग की सीटों पर बसपा की सफलता में सामाजिक अभियांत्रिकी का योगदान रहा। सामान्य वर्ग की सीटों पर बसपा प्रत्याशी चयन में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक ढांचे के प्रति बेहद सजग रही और उस जाति के प्रत्याशी के चयन को प्राथमिकता दी जा उस विधानसभा में बहुल्य में थी ताकि बाहुल्य जाती व दलितों का गठबंधन वांछित सफलता प्राप्त कर सके। चूंकि दक्षिण राजस्थान के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को छोड़कर दलित सभी विधानसभा क्षेत्रों में 20000 से लेकर 40000 मतदाताओं के रूप विद्यमान है।

लोकसभा निर्वाचनों में बसपा का प्रदर्शन विधानसभा निर्वाचनों की अपेक्षा बहुत कम रहा है। यद्यपि उत्तरोत्तर रूप में इसके समर्थन में वृद्धि हुई है। राजस्थान में बसपा इकाई के औपचारिक रूप से कार्य करने के बाद सर्वप्रथम 1998 में बसपा ने लोकसभा निर्वाचन में उम्मीदवार खड़े किए। 1998 के लोकसभा निर्वाचन में बसपा ने 25 सीटों में से 22 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए और 2.12 प्रतिशत मत प्राप्त किए। 1999 के लोकसभा निर्वाचन में बसपा ने 16 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से अपने प्रत्याशी घोषित किए और 2.7 प्रतिशत मत प्राप्त किए। इसी प्रकार 2004 के निर्वाचन में बसपा ने 18 उम्मीदवार घोषित किए और 2.9 प्रतिशत मत प्राप्त किए। 2009 के लोकसभा निर्वाचन में बसपा ने 16 लोकसभा सीटों पर निर्वाचन में भाग लिया और 3.37 प्रतिशत मत प्राप्त किए। लोकसभा निर्वाचन में कांग्रेस व भाजपा के बाद बसपा ने सीमित मत प्राप्त करने के बावजूद तीसरी शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

पिछले तीन विधानसभा व लोकसभा निर्वाचन में बसपा के प्रदर्शन का तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट होता है कि विधानसभा निर्वाचन की अपेक्षा लोक सभा निर्वाचन में बसपा का प्रदर्शन लगभग आधा रह जाता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोक सभा निर्वाचनों में तुलनात्मक प्रदर्शन कमजोर क्यों रहता है ? हालांकि इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा कठिन है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के आधार पर संगत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रथम – लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से असमान होते हैं। एक लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्र से मिलकर बनाया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार के साथ ही सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हो जाता है। द्वितीय – लोकसभा निर्वाचन में बसपा अपने प्रत्याशी को जीतने योग्य सामाजिक अभियांत्रिकी का फार्मूला नहीं बना पाती है।

तृतीय – विधानसभा निर्वाचन में सामाजिक अभियांत्रिकी के फार्मूले से गैर दलितों का पर्याप्त समर्थन मिल जाता है लेकिन लोकसभा निर्वाचन में विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र व बदली सामाजिक संरचना के कारण दलितों का समर्थन बेहद नगण्य हो जाता है। चतुर्थ— बसपा प्रत्याशी के लोक सभा निर्वाचन में जीतने की कम संभावना के कारण बसपा का कुछ दलित वोट अन्य दलों की तरफ चला जाता है। पंचम— विधानसभा क्षेत्र छोटा होने के कारण प्रत्याशी सामाजिक व राजनीतिक रूप से व्यक्तिगत प्रभाव रखता है जिससे वह अधिक समर्थन हासिल करता है। लेकिन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र विस्तृत होने के कारण प्रत्याशी अन्य क्षेत्र में अपना व्यक्तिगत प्रभाव नहीं रखता है।

अतः इन सभी कारणों का एक स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि एक राजनीतिक दल जो अपने को स्थापित करने की प्रक्रिया में संलग्न हो, विधानसभा निर्वाचनों की अपेक्षा लोक सभा निर्वाचन में कमजोर प्रदर्शन करता है।

सन्दर्भ :-

1. अम्बेथ राजन, माई बहुजन समाज, नई दिल्ली, 1994
2. एस.के.वर्मा 'भारतीय लोकतंत्र में समावे'ी राजनीति, सीएसडीएस, नई दिल्ली 2006
3. बसपा चुनाव घोषणा पत्र 2008